REFERENCE TO NOTICE FOR RAISING A MATTER OF PUBLIC IMPORTANCE

MR. CHAIRMAN: Shri Bhishma Narain Singh.

SHRI SANKAR GHOSE (West Bengal): Sir, on a point of order. There is a notice I had given on a matter of great public importance and a threat to the democratic functioning of State Government.

MR. CHAIRMAN: That is all right but . . .

SHRI SANKAR GHOSE: On that the notice has been disallowed. I find that my notice has been clubbed with eight other notices. Some notices have been allowed and some disallowed. My notice was not on the Governor of Maharashtra. My notice was that there is grave apprehension that certain elements in the Central Government are trying to pressurise the Governor of Maharashtra... (*Interruptions*).... This kind of pressurisation will render our elections a complete mockery and render our democratic functioning a farce. Therefore, I have given this notice. I had not given a notice on the Governor of Maharashtra. I am told pressure is sought to be brought on the Governor so that President's rule is imposed so that the person who has the majority in the elected legislature is not called. This is the first time where the Governor has been satisfied fully. Every person has been present before him and they have been shown and, in spite of that, he is not being called. And the reason is, pressure is brought from here and this pressure from here should cease altogether. Unless this is.... (*Interruptions*). . . .We will walk out of the House.

[*At this stage some hon. Members left the Chamber*].

SHRI BHISHMA NARAIN SINGH: Sir,...

SHRI BHUPESH GUPTA (West Bengal): Sir, I have a submission to make. The matter is one . . .

MR. CHAIRMAN: I have admitted, but if you do not allow him, what can I do?

SHRI BHUPESH GUPTA: The matter is one...

MR. CHAIRMAN: I have admitted special mentions and they are there to speak.

SHRI BHUPESH GUPTA: On this point?

MR. CHAIRMAN: Yes.

SHRI BHUPESH GUPTA: It is all right, they will speak. I only say that some of our friends have walked out.

MR. CHAIRMAN: That is all right. But there are others who are there on the list.

SHRI BHUPESH GUPTA: All right.

MR. CHAIRMAN: Shri Bhishma Narain Singh.

REFERENCE TO ALLEGED DELAY IN THE FORMATION OF GOVERNMENT IN MAHARASHTRA

श्री भीष्म नारायण सिंह (बिहार) : सभापति महोदय, मैं बड़े दु:ख के साथ आज के लगभग सभी समाचार पत्रों में जो समाचार छपा है, उसकी तरफ

[Mr. Deputy Chairman in the Chair]

आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इसका सम्बन्ध महाराष्ट्र में सरकार बनाने से है। आज के एक समाचार पत्र में जो छपा है, उसके एक पोर्शन को मैं यहां पर उद्धृत करना चाहता हूं। आज के 'टाइम्स आफ इंडिया' में निकला है कि:

"The issue of formation of a new government in Maharashtra remain-

ed undecided till late tonight as the Congress and the Janata blocs continued to make conflicting claims regarding support from the newly elected members of the 288-strong legislative assembly.

While the Congress and the Congress (I) together presented a total of 149 members who signed declarations before the Governor, Mr. Sadiq Ali, the Janata Party submitted a list of 145 members who have pledged support to a Janata coalition ministry."

उपसभापति महोदय, मुझे यह कहना है कि आपने देखा होगा कि आज तक इन 30 वर्षों में विभिन्न दलों की सरकारें बनी। हमारे राज्य बिहार में भी 1967 में बनी। उपसभापति महोदय, उस समय 318 सदस्यों की विधान सभा में कांग्रेस के 128 सदस्य थे। हम लोग विपक्ष में बैठें। विरोधी दलों ने एक युनाइटेड फ्रंट बनाया था जिसका कि बहुमत था। राज्यपाल महोदय ने युनाइटेड फ्रंट के लीडर के रूप में श्री महामाया प्रसाद सिन्हा के दावे को स्वीकार किया और उन्हें सरकार बनाने को कहा।

जनता पार्टी के नेता दिन रात इस बात का प्रचार करते हैं कि उन्होंने आजादी बहाल कर दी है, प्रजातंत्र को फिर से लौटा दिया है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि क्या प्रजातंत्र को लौटाने का यही उदाहरण है?

(*Interruptions*)

उपसभापति जी, मैं कहना चाहता हूं और आप मेरी इस बात पर जरा ध्यान दें कि आज जनता सरकार में फासिस्ट एलीमेन्ट बठे हुए हैं। इसलिये मैं आपके सामने कहना चाहता हूं कि मैं बिहार विधान सभा में सदस्य था। आपने सुना होगा कि उस समय जो इलेक्टेड रिप्रेजेनटेटिव थे, उनके इस्तीफे की मांग की गई है। संविधान में कहीं भी रिकाल की व्यवस्था नहीं है। उस समय उस सरकार को जनता का विश्वास प्राप्त था परन्तु फिर भी उसका इस्तीफा मांगा। वैसे ही तत्व इस सरकार में बैठे हुए हैं। ये अधिनायकवादी तत्व प्रजातंत्र का गला घोंटने वाले हैं।

(*Interruptions*)

मुझे अभी बम्बई से सूचना मिली है। मैं आपको विधायक का नाम बताना चाहता हूं श्री गडूर जो इन्डिपेंडेंट मेम्बर है और वे हमारी पार्टी का समर्थन कर रहे हैं और उनका नाम 149 लोगों में है। वहां के राज्यपाल अपने कार्यो द्वारा इस पद की गरिमा को घटा रहे हैं। राज्यपाल वहां इस सदस्य को यह कहते हैं कि आप जनता पार्टी को क्यों सपोर्ट नहीं कर रहे है? इसलिये मैं आपसे कहना चाहता हूं कि वह कर्नाटक के राज्यपाल श्री गोविन्द नारायण जी का अनुकरण कर रहे हैं; इसलिये हमारी मांग है कि सरकार इस बात की अविलम्ब जानकारी दे। प्रजातंत्र और संविधान का जो मखौल उड़ाया जा रहा है, यह न होने दें। आप डेमोक्रेसी के कस्टोडिन है, इसलिये मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप सरकार को तुरन्त कहें कि वहां पर सरकार बनाने में क्या दिक्कत है और इस बात की जानकारी दें कि जब 288 के सदन में 149 फिजिकली प्रेजेन्ट हो गये हैं, तो फिर श्री बसंतराव पाटिल को, जो कि उस पार्टी के लीडर हैं, उनको सरकार बनाने के लिये निमंत्रण क्यों नहीं दिया जा रहा है। हम इस सवाल पर सरकार से अविलम्ब यहीं पर उत्तर चाहते हैं।

श्री श्यामलाल यादव (उत्तर प्रदेश): मान्यवर, मैं इस मांग का समर्थन करते हुए केवल एक-दो बातें निवेदन करना चाहता हूं। जनता पार्टी ने ऐलान किया है कि हम जनतंत्र में विश्वास करते हैं और 1977 में उनका यह ऐलान चमत्कार लाया। मैं उनसे यह पूछना चाहता हूं कि क्या यही जनतांत्रिक तरीका है कि जो नेता विधान सभा में बहुमत वाली पार्टी का हो, उसको सरकार

[श्री श्याम लाल यादव]

बनाने का निमंत्रण न दिया जाय। यह एक अभूतपूर्व घटना है और ऐसी घटना है जिस पर भारत की जनता का सर झुक जाता है। इसके लिये सरकार की जितने भी कड़े शब्दों में भर्त्सना व निन्दा की जाये वह कम है। यह बहुत ही अफसोस की बात है वहां पर एक केन्द्रीय मंत्री बैठे हुए हैं, राज भवन में बैठे हुए हैं और वहां बैठ कर सदस्यों की खरीद-फरोख्त कर रहे हैं। इस बात का प्रयास किया जा रहा है. . . (*Interruptions*) मेम्बरों को खरीद कर के, रुपये दे कर के महाराष्ट्र सरकार बनाई जाये। एक तरफ तो गवर्नर सादिक अली के सामने परेड कराई गई। मैं गवर्नर सादिक अली से पूछना चाहता हूं केन्द्र सरकार के गृह मंत्री की यह कौनसी तानाशाही है, कौन सा तरीका है, संविधान की कौनसी मान्यता है, कौनसी नैतिकता है, कौनसा समर्थन आपके पास है. . . (*Interruptions*) बहुमत दल के नेता को सरकार बनाने के लिए निमंत्रित नहीं किया जा रहा है। जनतंत्र की हत्या की जा रही है। संविधान की निर्मम हत्या की जा रही है। ऐसे अत्याचार किये जा रहे हैं तो मैं सरकार को बता देना चाहता हूं कि इस सदन की कार्यवाही को हम नहीं चलने देंगे। अगर सरकार अपने. . . (*Interruptions*) बैठ कर प्रदेश की सरकारों को बनाने का प्रयास और फिर उस पर पर्दा डालते हैं। हम इस सरकार का विरोध करेंगे। हम सदन को नहीं चलने देंगे। यह अनैतिक कार्य है, असंवैधानिक कार्य है। यह परम्पराओं और मर्यादाओं के विपरीत है। मैं जनता पार्टी के नेताओं से पूछना चाहता हूं। श्री लाल कृष्ण आडवाणी जब इधर बैठा करते थे सिद्धान्तों की चर्चा किया करते थे. . (*Interruptions*) आज वे भूल गये। सरकार में आने पर वे मदमस्त हो गये, इतना अहंकार हो गया, मद के नशे में इतने चूर हो गये कि न्याय को भूल गये, इन्साफ को भूल गये, परम्पराओं को भूल गये, अपने बयानों को भूल गये, यह इसका प्रमाण है। मान्यवर, कहा जा रहा है कि जिस दल के सदस्यों की संख्या अधिक हो, चाहे वह अल्पमत का दल ही क्यों न हो, उसको सरकार बनाने का मौक़ा दिया जाये। मैं पूछना चाहता हूं क्या देश में कभी ऐसा हुआ है। अभी बिहार का उदाहरण दिया गया. . . (*Interruptions*)

श्री नत्थी सिंह (राजस्थान) : राजस्थान में. . . (*Interruptions*) यू० डी० एफ० गवर्नमेंट की परम्परा कांग्रेस ने कायम की. . . (*Interruptions*)

श्री श्याम लाल यादव : बहुमत दल के नेता को अगर सरकार बनाने के लिए आमंत्रित नहीं किया जाएगा तो हम यह कहना चाहते हैं कि हम सरकार को नहीं चलने देंगे। सदन की कार्यवाही को नहीं चलने देंगे . . . (*Interruptions*) सदन की कार्यवाही नहीं चलेगी।

एक माननीय सदस्य : लोकतंत्र के दुश्मन हैं. . .

श्री उपसभापति : श्री श्रीकांत वर्मा।

SHRI BHUPESH GUPTA (West Bengal): I want to make a submission on this subject.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: We will not permit other people to participate in this as a sort of a debate. Only the persons who have been permitted to speak will speak.

श्री श्रीकान्त वर्मा (मध्य प्रदेश) : उपसभापति महोदय, जनता पार्टी ने. . . (*Interruptions*)

श्री रामानन्द यादव (बिहार) : यह एक महत्वपूर्ण विषय है। हम लोगों को और सदस्यों को बोलने दिया जाए . . .

(*Interruptions*)

श्री श्रीकान्त वर्मा : उपसभापति महोदय जनता पार्टी आजादी और संविधान के मामले पर सत्ता में आई थी... (*Interruptions*) मैं जोर से चिल्ला कर बोलना नहीं जानता और मैंने यह बहुत कम सुना है कि रूलिंग पार्टी के लोग इतने जोर से चिल्ला-चिल्ला कर, इतने बड़े मसले में व्यवधान पैदा करें।

श्री नत्थी सिंह : हमने तो समय पर किया. . . (*Interruptions*) ऐसे समय फैसला किया मजबूरी में . . .

(*Interruptions*)

श्री श्रीकान्त वर्मा : सत्ता में आने के केवल तीन महीने के अन्दर जनता सरकार ने 9 राज्यों में विधान सभाओं को भंग करवा दिया, जहां कि कांग्रेस का बहुमत था। वहां पर कांग्रेस पराजित हुई और हमने जनमत को स्वीकार किया; क्योंकि हम जनमत का आदर करते हैं। हम यह उम्मीद करते थे कि आज महाराष्ट्र में जनता ने जो फैसला दिया है, जनता पार्टी उसका आदर करेगी। लेकिन ऐसा लगता है कि जनता पार्टी उसका आदर करने को तैयार नहीं है। यह बात सत्य है कि गवर्नर सादिक अली पर या तो केन्द्र से दबाव डाला जा रहा है या फिर अगर केन्द्र से दबाव नहीं डाला जा रहा है, तो वे बिल्कुल पक्षधर ढंग से कार्य कर रहे हैं। उपसभापति महोदय, श्री श्रीधर महादेव जोशी, जो जनता पार्टी के एक बड़े कार्यकर्ता हैं, गवर्नर के पास गये और उन्होंने कहा कि नुमेरिकल स्ट्रेन्थ या संख्या काफी नहीं होती है बल्कि इस बात को देखना होता है कि सबसे बड़ी पार्टी कौन सी है। यह तर्क पिछले 32 सालों से आज तक स्वीकार नहीं किया गया है; क्योंकि सन् 1967 में अनेक जगहों पर कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी के रूप में चुन कर आयी थी, लेकिन फिर भी उसे सरकार नहीं बनाने दिया गया। जबकि केन्द्र में कांग्रेस सरकार थी फिर भी अनेक जगहों पर संयुक्त विधायक दलों ने सरकारें बनायीं।

दूसरे यह काम श्री श्रीधर महादेव जोशी या कि गवर्नर का नहीं है कि कौन सी सरकार स्थायी हो सकती है? इसका फैसला तो जनता करेगी। फैसला कल होगा, अगर नहीं होता है तो यह सरकार गिर जायेगी। लेकिन मैं यह जनाना चाहता हूं कि उनको क्या आपत्ति है जबकि 149 सदस्य परेड किये जा चुके हैं, दिखाये जा चुके है, दस्तखत कर चुके हैं। फिर उन्हें श्री वसन्त दादा पाटिल, जो कि संयुक्त विधायक दल के नेता हैं, को आमंत्रित करने में क्या दिक्कत है। साफ जाहिर है कि श्री सादिक अली की नीयत खराब है। मैं श्री भूपेश गुप्त जी से पूरी तरह सहमत हूं कि इस विषय पर विचार होना चाहिए; क्योंकि राज्यपालों को इस तरह से आचरण करने का कोई अधिकार नहीं है। हमारे पास और कोई तरीका नहीं है कि राज्यपाल की जो पक्षधर हो जाते हैं, निन्दा करें। सिवाय इसके कि हम उस पर विचार करें। मैं श्री भूपेश गुप्त के प्रस्ताव का पूरी तरह समर्थन करता हूं कि सदन को श्री सादिक अली के आचरण पर विचार करने का और बहस करने का पूरा मौका दिया जाय। जब तक यह नहीं होता है तब तक केन्द्र सरकार यह देखे कि वहां जो कुछ हो रहा है वह ठीक-ठीक हो। अगर नहीं देख सकती है तो जैसा कि समाचार आ रहे हैं बम्बई से, कि वहां लोगों का मनोबल गिरा हुआ है, उन लाखों, करोड़ों लोगों का, जिन्होंने चाहे कांग्रेस (आई) या कांग्रेस को मदद दी है, मन बेचैन होगा। जब वहां शांति व्यवस्था भंग होगी तो कहा जायगा कि कांग्रेस (आई) या कांग्रेस वालों ने यह शांति व्यवस्था भंग करायी है। लेकिन

[श्री श्रीकान्त वर्मा]

वास्तविकता यह है और मैं जानता हूं कि महाराष्ट्र को लड़ाकू जनता इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी, शांति और अमन भंग हो जायेगा तो इसकी जिम्मेदारी केन्द्र सरकार पर ही होगी, श्री सादिक अली पर ही होगी। अगर श्री सादिक अली संसदीय आचरण नहीं करते हैं तो केन्द्र का यह कर्त्तव्य है कि वह तुरन्त उनको बर्खास्त करे। अगर केन्द्र वाकई चाहता है कि उसकी प्रतिष्ठा लोकतांत्रिक सरकार के रूप में कायम हो तो सबसे पहले वहां वह उस सरकार को बनने दे जिसका कि बहुमत है और जो बहुमत प्रदर्शित किया जा चुका है। दूसरे वह श्री सादिक अली के विरुद्ध कार्यवाही करे। विशेषकर इसलिए भी कि श्री सादिक अली ब्यूरोक्रेट नहीं थे वह कोई सामाजिक व्यक्तित्व नहीं थे, बल्कि वे राजनीतिक हस्ती हैं, उनका एप्वाइंटमेंट पोलिटिकल है। ये पोलिटिकल एप्वाइंटमेंट रद्द किए जायें, चाहे वे गोविन्द नारायण के हों या सादिक अली के। धन्यवाद।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Shri Deorao Patil.

SHRI DEORAO PATIL (Maharashtra): Sir, I am thankful to you for permitting me to raise an issue of urgent public importance, namely, "Reported delay in formation of a new Government in Maharashtra and delay in clearance by the Governor even after parading and pleading of support by 149 MLAs belonging to the Congress Front."

उपसभापति महोदय, महाराष्ट्र की विधान सभा 288 सदस्यों की है। वहां के 149 नव निर्वाचित एम० एल० एज० ने कल राज्यपाल श्री सादिक अली की उपस्थिति में महाराष्ट्र राज्य सरकार के कांग्रेस मोर्चे के मंत्रि मंडल को समर्थन देने की घोषणा पर हस्ताक्षर किये। राज्य भवन में मैं खुद भी उपस्थित था। उपसभापति जी, राज्यपाल ने अपने कक्ष में 19 निर्दलीय सदस्यों को स्वयं अलग बुलाया जैसा कि एक माननीय सदस्य ने शिकायत की कि राज्यपाल ने कन्वेंसिंग करने का काम भी किया ऐसा हमें पता लगा है। निर्दलीय सदस्य को अपने कमरे में मिलने के बाद, सारे 149 सदस्यों को एक के बाद एक करके बुलाया था। प्रत्येक विधायक ने कांग्रेस मोर्चे के मंत्रिमण्डल को समर्थन देने के शपथ पर हस्ताक्षर किए, उनकी फोटो खींची गई, हर एक का फोटो लिया गया। प्रत्येक विधायक ने कांग्रेस मोर्चे की सरकार बनाने के लिए कांग्रेस विधायक दल के नेता श्री वसंत दादा पाटिल को मंत्रिमण्डल बनाने को कहा जाने के लिये और राज्यपाल से प्रार्थना की, राज्यपाल से कहा कि वह उसके बारे में तुरन्त अपना निर्णय दें। सदस्यों ने इस बात पर बहुत जोर दिया कि राज्यपाल अपना निर्णय तुरन्त घोषित करें। यह काम पेंडिंग में रखना ठीक नहीं है, अगर उन को कुछ टाइम चाहिए, आध घंटा, एक घंटा, दो घंटा, वह टाइम ले लें लेकिन निश्चित टाइम हमें दे दें कि इस वक्त राज्यपाल वसंत दादा पाटिल को बुला लेंगे। सदस्यों ने राज्यपाल को यह बताया कि सेंट्रल गवर्नमेंट के मंत्री जो बम्बई में उपस्थित हैं वह निर्दलीय मेम्बर्स पर दबाव डाल रहे हैं मंत्री महोदय ने राज्यपाल से कहा है कि ज्यादा फर्क नहीं है पांच-दस का फर्क है, हमें टाइम दीजिए और इसी लिए राज्यपाल निर्णय टाल रहे हैं। कोई निर्णय न लेने का जो स्टैंड सादिक अली ने लिया वह इसलिए लिया कि जनता पार्टी के नेताओं ने टाइम मांगा है, इसलिए राज्यपाल टाइम लगा रहे हैं। राज्य भवन में मीटिंग होने के बाद सादिक अली से सदस्यों ने कहा कि हम 149 लोग यहां से नहीं जाएंगे, हमें निर्णय जो देना है दे दीजिए। उन्होंने कहा हम निर्णय लेकर ही जायेंगे और निर्णय कोई दूसरा निर्णय नहीं हो सकता है। तो हमने सदस्यों को समझाया। सदस्य राज भवन

में ही बैठने की कोशिश कर रहे थे, यानी वहां से भवन छोड़ने का उनका इरादा नहीं था। तो कांग्रेस पार्टी के दोनों नेताओं ने सदस्यों को समझाया एवं उन्होंने राज भवन छोड़ा।

उपसभापति जी, मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि आज हमने यह सुना कि जनता पार्टी के नेताओं ने बम्बई में आज 5 बजे अपनी पार्टी के बहुमत के सिलसिले में एक जाहिरा सभा बुलायी है जिसमें गवर्नर साहब पर दबाव डालना चाहते हैं। कल आपको पता होगा उपसभापति जी, कि कांग्रेस और इंदिरा कांग्रेस के नेताओं की तरफ से एक डेपुटेशन राष्ट्रपति से मिला। राष्ट्रपति ने भी एक अनुकूल रुख दिया। उन्होंने कहा, हम पंच प्रधान से बातचीत करेंगे। उपसभापति जी, गवर्नर साहब ने निर्दलयीय सदस्य को खुद बुलाया अपने सामने और उनके दस्तखत लिए, शपथ लिया, अब सिर्फ 115 लोग जनता पार्टी के साथ हैं--जनता पार्टी और उनकी जो अलाइड पार्टीज हैं उनके सिर्फ 115 सदस्य हैं उसके बावजूद भी जो गवर्नर साहब बहु- संख्यक पार्टी को बुलाने में डिले कर रहे हैं तो Persistent refusal of the Governor to invite the majority party to form a Government is a standing disgrace. It is perversion of the Constitution. This is the greatest blow to the democratic framework of our political life. If a Governor who is supposed to be impartial, abuses his position to advance the party to which he belongs, such Governor should be dismissed by the President immediately.

उपसभापति जी, यह गम्भीर मामला है। राज्यपाल से इस में देर लग गयी तो मैं जनता पार्टी के माननीय सदस्यों को और हमारे सदन के नेता श्री आड़वाणी साहब, उनसे नम्रतापूर्वक प्रार्थना करूंगा कि जनता ने जो अपना ओपीनियन दिया है उसको मान लीजिए--वार्डिक्ट आफ दि पीपुल शुड बी आनर्ड। अगर यह नहीं हुआ तो महाराष्ट्र की जनता उठ खड़ी होगी। कल ही 149 विधायक लोग इतने उग्र हो गए थे कि वहां स्थिति को संभालने में हमें कठिनाई का सामना करना पड़ा, इसमें देर लगेगी तो महाराष्ट्र में आग भड़क जाएगी और उसका सारा भार, उसकी जिम्मेवारी भारत सरकार पर आएगी। मैं फिर नम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा अडवाणी साहब से कि जल्द से जल्द इस बारे में पहल करें और वसंत दादा पाटिल को मंत्रिमंडल बनाने दें। स्टेबिल गवर्नमेंट की जो बात चल रही है। जनता पार्टी के सिर्फ 98 और हमारे दोनों ग्रुप मिला कर 143 सदस्य हैं। तो ऐसी हालत में हमारी स्टेबिल गवर्नमेंट बन सकती है। अगर केन्द्र सरकार महाराष्ट्र में कोई स्टेबिल गवर्नमेंट बनाना चाहती है तो आगे जो करना हो वह करे, लेकिन जब हमारी मेजारिटी वहां हो गयी है तो फिर आप देरी क्यों कर रहे है। (*Interruptions*) इसलिए मेरा कहना है कि इस में पार्टी का ध्यान न रखा जाय और कांस्टीट्यूशन का ध्यान रखते हुए जनता सरकार इसमें दिलचस्पी ले और इसका निर्णय आज ही कराये।

श्री यशपाल कपूर (उत्तर प्रदेश) : आज नहीं, अभी।

SHRI BHUPESH GUPTA: I rise to express my opinion and also to call upon the Government to make its position clear. I think this is a fit matter for this House to be seized of and take up as a separate subject immediately for discussion. Therefore, my suggestion to the House and to you in particular is to permit me to move a Resolution of this kind:

> This House do waive the Rules of the House to take up immediately the discussion on the serious Constitutional situation which has arisen in Maharashtra and which

[Shri Bhupesh Gupta]
involves the Constitutional propriety, convention and practices on the issue of the formation of a new Ministry.

Why do I want it? Because we are the Council of States. Something is happening in the State and we are entitled to have a thorough discussion and also to have the opinion of the Government. It is a serious matter and cannot be dealt with in a casual manner, much as I would like to have as in other cases. But it is for the Government to come and tell us why there is this delay in the formation of the Government in Maharashtra and why the Governor, who is supposed to be the agent of the Centre, is not acting properly. This has to be explained. We are all the more apprehensive because last night, it seems, there was a meeting in the Prime Minister's house in which Shri S. M. Joshi, Shri Nanaji Deshmukh, Shri Madhu Limaye, Shri Mohan Dharia, Shri Patil, the Minister of State and Shri Shanti Bhushan took part in the discussion on the Maharashtra situation, and at 1 A.M. a telephone call is reported—I repeat reported—to have gone from the Prime Minister's blessed house—or the Prime Minister's house—I thought that name would not be used—to the Governor of Maharashtra, our friend there. He was a Member of this House. First of all, I want to make it clear that I do not like the parading business of M.L.As. before the great Governor of Maharashtra, Shri Sadiq Ali. I do not like it at all. This practice is very bad. Now, what do we go by? I will give you the example of the United Front in 1967. We formed two separate fronts of the left Parties. We were in one front. Shri Ajoy Mukherjee was on that front. The CPI(M) also led another front. Both the fronts together got a majority. Against that, the Congress had a big majority also. What happened? After the elections were fought separately, these two fronts came together —I participated in that meeting—and decided that they will approach the Governor on the basis of their joint stand to demand that their leader be called upon to form the Government. The Congress Party opposed it on the ground that neither front—the CPI (M) left front or the front in which we and the Bangla Congress were there—had a majority. And, therefore, they said that we should not be called. On the contrary, it was the Congress Party which claimed to have the largest number of members, though not a majority, and which said that it should be called to form the government. Sir, this matter was debated. It came up here also. Ultimately, within a short time, the Governor, while acting in the case, took the decision, and I think a correct decision was taken since these two parties and fronts came together. Mind you, it was not just two parties which came together, but many parties; twelve or thirten parties came together and produced a joint front showing the majority of members, who belonged to the parties and who belonged to the groups, which had chosen their leader for being invited by the Governor to form the government there and the Governor thought that the leader, namely, Shri Ajoy Mukherjee, should be invited and Shri Ajoy Mukherjee was invited. Sir, Dr. Pratap Chandra Chunder is here. He will bear me out on the question of this at least though he may not share my views. Everybody undergoes a change these days. He is an honourable man and a truthful man. Perhaps by chance he is in the Janata Party. But I am not going into all these details now. Now, Sir, nobody would dispute it. You will not dispute it because many of the friends sitting there were sitting on this side then and they were not only supporting it, but also they were demanding that this combination should be allowed to form the government and it was done Sir, that practice was followed in other States also. Remember, after the 1967 elections, 9 non-Congress governments were formed in the country and in most of the cases there was no single party majority and such combinations took place and these combi-

nations claimed that on the basis of the number of members they had, they should be allowed to form the government and the Governors, even in those days, had to agree to such a demand. This is how it was done in those days. Sir, we have certain conventions, we have certain practices, and we should follow them. I am not interested in the party thing at all. I am here now on the issue of constitutional propriety, conventions and practices that we have followed. Are we to go by them or not? What happened in Madhya Pradesh then? Sir, if you look back, you will find that in comparable situations, things have not gone the way things are going in Maharashtra today. Obviously, other extraneous considerations have intervened: other things have intervened and this I find because the Governor is delaying it.

Sir, we are against the President's Rule. There must not be any President's Rule in Maharashtra. Why? Because there are people who are ready to give a majority. The Constitution does not mention even "party". The Constitution says that a government can be formed by a group which has the majority. Sir, the Governor, under the relevant articles of the Constitution, has got discretionary powers in the matter of invitation being issued to a person after the elections, to form the government. Now, Sir, how the Governor is exercising that discretionary power under the relevant provisions of the Constitution is also a point to be taken into account. How should the Governor be satisfied? By the known facts. The known facts are that? They are shown in the election results. There are now two parties: The Congress Party and the Congress led by Shrimati Indira Gandhi The two parties have won a number of seats. Add up these seats and these seats together give them a majority or a near majority or some such thing whereas the other party, even alongwith those who are supporting it, does not have a majority and even their number does not go to a higher number than the one shown by the combination of the two Congress Parties. Sir, this is an established fact, a fact established by the election results, reported in the newspapers and not disputed by any leader. Even the Janata Party leader has not claimed that some of the Congress people, whether from the Indira Congress or the other Congress, would come to them. No. Has he said that? No. He has not said. He is proceeding on the basis that he has got some people with him and some more will be there and he has also got the support of the CPM perhaps. But is this the way? Is this the way the Governor should act? I am not saying at this moment how the Governor should act. But he should act on this basis: (1) election results, (2) known fact of combination of two parties, namely, Congress Party and Congress (I), and (3) their total number. The Governor should go by the precedent which had been followed in other States. That is why, I think, the first invitation of the Governor should go to the person nominated by the combination rather than by the Janata Party. The Government should summon the Assembly and assess the majority there. Assess the majority, not in the Governor's House, in the Raj Bhavan. Let the majority be tested on the floor of the House.... *(Interruptions)*. That should be the Governor's approach. That is the democratic approach. Why Governor Sadiq Ali is not taking that step, I do not know. He should summon the Assembly immediately and ask the Chief Minister to prove his majority there... *(Interruptions)*. Why is that not being done? Why? Obviously, this raises grave doubts, apprehensions, manipulations... *(Time bell rings)*. I had told my friends who were on this side then: Do not do such things otherwise you will be the victims. I have lived long enough in this House to see my friends on this side of the House, who would not listen to my good reasoning and argument, become victims of the monster of strikes.

AN HON MEMBER: Live long.

[Shri Bhupesh Gupta]

SHRI BHUPESH GUPTA: Such is the.... (*Time bell rings*). This is how destiny takes its revenge. And, Sir, Mr. Advani, with his lovely face, is putting up a sweet smile. I am told that an R.S.S. man is going to be the Chief Minister of the Maharashtra State.. ..(*Interruptions*). Strangely enough, painfully enough, I have to bear the sight of my good comrades of the C.P.M. supporting and installing an R.S.S. Chief Minister.... (*Interruptions*). I am not at all agitated. It pains me. The whole thing is becoming more and more mysterious and highly intriguing, violative of the constitutional practices and conventions, defying democratic norms and defying what had been valued in the past in some cases even under the Congress regime. Is that how you are dismantling the emergency? Good things you are demolishing, and bad things are becoming your assets. You are accepting them as assets. Mr. Shanti Bhushan, you have come here after fighting in a court of law . . .

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please wind up.

SHRI BHUPESH GUPTA: I am actually wound up. But before democracy is wound up, in the name of restoring democracy, let me have my say. Who does not know, Sir, that Mr. Charan Singh mooted a Bill in the Cabinet and he wanted to provide that all industries and services in Delhi be declared as essential services so that strikes could be declared illegal and he proposed that all those who go on strike should be automatically dismissed and they should loss their jobs?.... (*Interruptions*). Sir, all these things are being secretly said. We never had such things. Therefore, I look at the whole business as a kind of conspiracy against democracy and parliamentary institutions. I hope Mr. Sadiq Ali who is a good friend of ours and has been a colleague in this House, would not be a party to it. He is my good friend. Mr. Sadiq Ali and his wife used to come to see me when I fell ill. I have personal regard, affection and emotion for him. May I send my appeal to him that in the name of democracy, he should not be involved in these manipulations? He should quit Raj Bhavan rather than do these kinds of manipulations. I have said enough. I do hope that the Government will make some statement. Don't sit like Gautam Buddha here: Please say something. Mr. Shanti Bhushan, I challenge you on constitutional, legal, moral and political plane. Why is the Governor behaving like this? Deny it if you are not in touch with the Governor. You have no business to be in touch with the Governor. The Governor should find facts himself. Deny if you have not talked to him over the telephone. Why should a deputation come from there and go from here? All these things are happening. We have only something about sports in the afternoon. We can just as well defer it. In the afternoon, we can take up this matter for discussion in the House. What is happening in Maharashtra?

श्री सीताराम केसरी : (बिहार) श्रीमन्, इन लोगों ने गांधी जी की समाधि पर कसम खाई थी...... (*Interruptions*)

SHRI BHUPESH GUPTA: That is what I will request the Government. Will the Government accept this challenge? Will Mr. Advani, Leader of the House, join with me and all of us in requesting you that the other business of the House be postponed for taking up this discussion? Or we can do it tomorrow. But today is the time. I think the Council of States is fully entitled to pay special attention to this matter.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please wind up.

SHRI BHUPESH GUPTA: Mr. Morarji Desai should be here.

I do not know where Mr. Charan Singh is.

श्री नत्थी सिंह : उपसभापति महोदय, मुझे इस बात की खुशी है कि उस तरफ के माननीय सदस्यों द्वारा इस तरह के सवाल यहां पर पूछे जा रहे हैं। उस तरफ के माननीय सदस्यों ने यह सवाल पूछा है कि...

(*Interruptions*)

श्री भीष्म नारायण सिंह : श्रीमन्, हम मंत्री जी से इन बातों का जवाब सुनना चाहते है?.....

(*Interruptions*)

श्री नत्थी सिंह : क्या इसी का नाम जनतन्त्र है.......

(*Interruptions*)

[*At this stage, some hon. Members sat on the floor near the Chair*]

अगर आप बहस चाहते हैं तो दूसरों को भी सुनें.....

(*Interruptions*)

श्री उपसभापति : माननीय सदस्य सरकार की तरफ से कुछ सुनना पसन्द करेंगे ?

THE LEADER OF THE HOUSE (SHRI LAL K. ADVANI): Sir, this was the time for Special Mentions and the established practice in this House is that only those who have given notice of that Special Mention are permitted to speak. But, you in your discretion, Sir, decided that this is a special matter and, therefore, permitted some other Members also to speak. And when you did permit them, I see no reason why the members belonging to the ruling party should not be allowed to speak. (*Interruptions*)

श्री नत्थी सिंह : उपसभापति महोदय..

(*Interruptions*)

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Order please. Shri Patil wanted to speak something. (*Interruptions*)

THE MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI SHANTI BHUSHAN): Sir, may I respectfully enquire whether this House is meant for debates or these cultural activities? (*Interruptions*).

SHRI BHUPESH GUPTA: I suggest that if the Minister wants to speak... (*Interruptions*) Sir, I can understand their anger against each other. But if the Minister wants to speak, is he speaking for the Government? May I ask the Leader of the House whether anyone that he chooses, will he be speaking for the Government?

In fact, I would like the...

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI S. D. PATIL): Mr. Deputy Chairman, Sir, the allegations made by the friends on the other side, who appear to be the new champions of democracy after emergency...

(*Interruptions*)

SHRI BHUPESH GUPTA: On a point of order, Sir. You have to guide us. He wanted to speak on questions of fact, on the Constitution, on convention, on law, the points that we have raised. We did not want him to deliver a lecture on emergency. (*Interruptions*).

SHRI S. D. PATIL: Some hon. Members made unwarranted allegations that some pressure is being brought to bear on the Governor of Maharashtra. (*Interruptions*). The Government or the Home Minister do not come into the picture except that the appointment of the Governor is made by the Home Ministry. We all know, Sir, that the Governor of Maharashtra, Mr. Sadiq Ali, has got a very good reputation as a public man. He is one of the rarest public men. We all know and Mr. Bhupesh Gupta knows that he is one of the finest men of this country, that he cannot be pressurised and that he will not act under any pressure.

SHRI N. G. RANGA (Andhra Pradesh): But he has behaved badly. (*Interruptions*)

SHRI S. D. PATIL: Please do not be impatient. The entire discretion in deciding this matter is that of the Governor. A list was submitted to the Governor by the two Congress Parties, containing 149 names, in which, Mr. Bhupesh Gupta, alleges that they had a clear majority. It consisted of 69—62 names, making it 131. Then there were some Independents, including Forward Block men and some people from the R.P.I. (Gavai) men. Nine Independents were also included. This was announced at 1.30 p.m. yesterday. The other party had also submitted a list. But in that list there were certain common names which the other side had pointed out. The other side submitted a list of 145 people. (*Interruptions*) The Governor has to satisfy himself whether in the list of 149 names there are not certain names which are common to both the lists. (*Interruptions*).

سید میر قاسم : (جموں و کشمیر) سوال یہاں یہ تھا کہ مہاراشٹر کی سچویشن نے ایک گمبھیر سچویشن پیدا کی (*Interruption*) جہاں تک اس کے بارے میں فیکٹس رکھنے کا تعلق تھا کانگریس (آئی) کے ممبرس نے فیکٹس کو رکھا یہ فیکٹس بالکل سادہ ھیں - (*Interruption*) دیکھئے اگر اپ انٹرپٹ کرنا چاھتے ھیں ایڈوانی صاحب آپ اپنے ممبروں کو بتائیے کہ وہ اس ھاؤس میں بزنس کنڈکٹ کرنے کے لئے ھم کو بولنے نہیں دینا چاھتے ھیں - (*Interruption*)

श्री नत्थी सिंह : निश्चित बात है कि इनमें कोई दम नही है. . यह घटियापन नहीं चलेगा, यह गुण्डागर्दी नहीं चलेगी ।

سید میر قاسم : معاملات ھمارے سامنے بڑے سادہ ھے - ۲۸۸ کا ایک ایوان ھے اس میں ۱۴۹ ممبر جب یہ کہتے ھیں کہ ھم کسی ایک لیڈر کے پیچھے ھیں تو صاف ھے کہ ۱۳۹ باقی رھتے ھیں کتنی پارٹیوں کے ھیں کس کے ھیں یہ دوسری بات ھے لیکن اکثریت کا معاملہ طے ھو جاتا ھے گورنر و کیا کرنا چاھئے کنسٹی ٹیوشن کی کیا پرا پرائٹی ھے اس میں بھوپیش گپتا جی نے اور دوسرے ممبرس نے بڑی وضاحت سے باتیں کی ھیں خیال یہ تھا کہ ھمیں معلوم ھے کہ ھمارے ذھن میں شک نہیں ھے کہ جو جنتا گورنمنٹ کی پالیسیز ھیں وہ کلیرلی لیڈ ڈاؤن ھیں - جن تمام رستوں سے ملک آگے بڑھا جن راستوں سے ملک نے آزادی پائی ترقی پائی اس راستے کو یہ اتنا ریورس کرنا چاھتے تھے - (*Interruption*)

If you want to interrupt me, I will not allow you. In fact, we are in a better position to interrupt you. You should listen to us and co-operate with us. (*Interruptions*)

آپ لوگوں کا آر - ایس - ایس کا طریقہ ھے - سوال یہ ھے کہ ان کو جگر تھام کو ھماری بات کو سننا چاھئے - تبھی ان کو موقعہ لگے گا ملک میں حکومت کرنے کا - اگر خیال یہ ھے کہ کسی کی زبان کو روک لیں ھم کو بات نہ کرنے دیں تو یہ مجبور کرینگے اکسٹرا کنسٹی ٹیوشن میتھڈ کی

طرف اس ملک کو دھکیلنے کے لئے
ہم نے مخالفت کی ہے کوشش کی ہے
کہ ہم راستہ اپنائیں - ہم نے راستہ
اپنایا ہے - ہمیں پورا احساس ہے -
سیکولرزم کے راستہ کا مہاتما گاندھی کو
قتل کرنے کے بعد ملک میں کیا ہوا
مہاتما گاندھی کو کس نے قتل کرایا-
یہ کوئی چھپی بات نہیں ہے - کتنے
پردے آگے لٹکائے -

Once the veils are pierced, the real faces become obvious.

لیکن وہ چھپانے کے طریقہ سے ہم
نہیں چاہیں گے کہ یہاں کے سیکولرزم
کو ریورس کیا جائے - اس ملک میں
جیسا کہ کل اس حکومت نے خود
کہا یہ خود کہتے ہیں کہ

They have brought back democracy on rails. It was derailed. A very happy and good intention.

لیکن انہیں کو کہتے ہیں - جس
پریس کی آزادی کی بات کو یہ
کہتے ہیں - انہیں کی گورنمنٹ نے
سدن میں یہ کہدیا ہے کہ سال میں
۱۵۲ کمیونل رائٹس ہو گئے -

1 P.M.

کیا ہیڈ لائنز کو ہو گیا - کیا
پریس کو ہو گیا - میں اس میں
جانا نہیں چاہتا - میں کہتا
ہوں سیکولرزم ریورس ہو رہا ہے -
اس کے ساتھ ہمارا پرائیویٹ اور
پبلک سیکٹر ریورس ہو رہا ہے -
اب چودھری چرن سنگھ صاحب -

ہم کر ڈیولیڈ نیشن سے ایک ڈیولپڈ
کنٹری رکھنے کے لئے پبلک سیکٹر کو
پرائیویٹ سیکٹر کو جائنٹ سیکٹر
کی بات کہہ کر پلان کو ہمارے ختم
کر رہے ہیں -

We will have a rolling Plan.

اب ایک بات اس ملک میں رہ
گئی تھی جس میں ہم ترقی کر سکتے
تھے - وہ ڈیموکریسی تھی ڈیموکریسی
میں یہ کیا انڈیکیشن ہے کہ

This is how they will wind up democracy also in this country.

ہم ان سے یہ ایکسپیکٹ رکھتے ہیں -
خاصکر میں مرار جی بھائی پرائم
منسٹر سے ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ
جو حالات اس وقت ہیں اس کے
پیش نظر - ہوم منسٹر سے تو میری
اتنی توقع نہیں ہے - لیکن ہم کل
پریزیڈنٹ سے ملے ہیں - پریزیڈنٹ
نے ہمیں یقین دلایا ہے کہ وہ پرائم
منسٹر صاحب سے بات کریں گے اور
گورنر کو کنوینینٹ کرنے سے ڈیلے کرنے
سے روکنے کے لئے پرائم منسٹر کو
کہیں گے - میں یہ عرض کرنا چاہتا
ہوں یا تو گورنمنٹ کی جانب سے
وہ اٹھکر کہدیں کہ ہم نے گورنر کو
انسٹرکشن دیئے ہیں --

to ask the elected leader to form the Government. If they convince us on this, we will stay in the House. Otherwise, we will walk out of the House. I do not want to hear any lectures or speaches from them.

[سید میر قاسم]

مختصر بات یہ ہے - کہا انہوں نے انسٹرکشنس دیئے ہیں گورنر کو کہ وہ ڈیمو کریسی کو ریسپیکٹ کریں تب تو میں اِن کی تقریر کو سننے کو تیار ہوں - اگر یہ کہنے کو تیار نہیں ہیں - وہ تو ہمیں معلوم ہے کہ یہی لوگ پریشوائز کر رہے ہیں - تو ہم تقریر سننے کو تیار نہیں ہیں -

†[सैय्यद मीर कासिम (जम्मू और काश्मीर) : सवाल यहां यह था कि महाराष्ट्र की सिचुएशन ने एक गम्भीर सिचुएशन पैदा की (*Interruptions*) जहां तक इसके बारे में फेक्ट्स रखने का तालुक था कांग्रेस (आई) के मेम्बर्सने फेक्ट्स को रखा—ये फेक्ट्स बिल्कुल सादा हैं—(*Interruptions*) देखिये अगर आप इन्ट्रप्ट करना चाहते हैं—आडवाणी साहब आप अपने मेम्बरों को बताइये कि वे इस हाऊस में विजनेस कंडक्ट करने के लिये हमको बोलने नहीं देना चाहते है

(*Interruptions*)

श्री नत्थी सिंह : निश्चित बात है इनमें कोई दम नहीं है (*Interruptions*) यह घटियापन नहीं चलेगा, यह गुंडागर्दी नहीं चलेगी ।

सैय्यद मीर कासिम : मामलात हमारे सामने बड़े सादा थे—288 का एक ऐवान है इसमें 149 मेम्बर जब ये कहते हैं कि हम किसी एक लीडर के पीछे हैं तो साफ है कि 139 बाकी रहते हैं—कितनी पार्टियों के हैं, किसके हैं ये दूसरी बात है लेकिन अक्सरीयत का मामला तय हो जाता है—गवर्नर को क्या करना चाहिए, कंस्टीटयूशन की क्या प्रोप्राइटी है—इसमें भूपेश गुप्ता जी ने और दूसरे मेम्बर्स ने बड़ी वजाहत से बातें की है—ख्याल यह था कि हमें मालूम है कि हमारे जहन में शक नही है कि जो जनता गवर्नमेंट की पालिसीज है वे क्लीयरली लेड डाऊन है—जिन तमाम रास्तों से। मुल्क आगे बढ़ा, जिन रास्तो से मुल्क ने आजादी पाई, तरक्की पाई उस रास्ते को ये इतना रिवर्स करना चाहते थ....

(*Interruptions*)

If you want to interrupt me, I will not allow you. In fact, we are in a better position to interrupt you. You should listen to us and co-operate with us. (*Interruptions*).

आप लोगों को आर० एस० एस० का तरीका है—सवाल यह है कि इनको जिगर थाम कर हमारी बात को सुनना चाहिये—तभी इनको मौका लगेगा मुल्क में हुकूमत करने का—अगर ख्याल यह है कि किसी की ज़बान को रोक लें हमको बात न करने दें तो ये मजबूर करेंगे एकसट्रा कंस्टीट्यूशन मैथड की तरफ इस मुल्क को धकेलने के लिये, हमने मेहनत की है, कोशिश की है कि हम रास्ता अपनाये—हमने रास्ता अपनाया है—हमें पूरा एहसास है सेक्युलरिज्म के रास्त का—महात्मा गांधी को कत्ल करने के बाद मुल्क में क्या हुआ—महात्मा गांधी को किस ने कत्ल कराया—यह कोई छिपी बात नहीं है—कितने पर्दे आगे लटकाइये—

Once the veils are pierced, the real faces become obvious.

लेकिन वो छिपाने के तरीके से हम नही चाहेंगे कि यहां के सेक्यूलरिज्म को रिवर्स किया जाये—इस मुल्क में जैसा कि कल इस हुकूमत ने खुद कहा—ये खुद कहते हैं कि

They have brought back democracy on rails. It was derailed. A very happy and good intention.

†[ ] Devanagri transliteration.

लेकिन इन्हीं को कहते हैं--जिस प्रेस की आज़ादी की बात को ये कहते हैं--इन्ही की गवर्नमेंट ने सदन में ये कह दिया है कि साल में 152 कम्यूनल राइट्स हो गये ।

क्या हेड लाइन्स को हो गया--क्या प्रेस को हो गया--मैं इसमें जाना नही चाहता--मैं कहता हूं सेक्यूलरिज्म रिवर्स हो रहा है--इसके साथ हमारा प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर रिवर्स हो रहा है--अब चौधरी चरण सिंह साहब हमको डेवेल्पड नेशन्स से एक अन्डर डेवेल्पड कन्ट्री रखने के लिये पब्लिक सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर को ज्वाइंट सेक्टर और एग्रीकल्चर सेक्टर की बात कह कर प्लान को हमारे खत्म कर रहे हैं ।

we will have a rolling plan.

अब एक बात इस मुल्क में रह गई थी जिसमें हम तरक्की कर सकते थे वो डेमोक्रेसी थी--डेमोक्रेसी में यह क्या इंडीकेशन है कि

This is how they will wind up democracy also in this country.

हम इनसे ये एक्सपेक्ट रखते हैं--खास कर मैं मोरारजी भाई प्राइम मिनिस्टर से एक्सपेक्ट करता हूं कि जो हालात इस वक्त हैं उसको पेशे नजर--होम मिनिस्टर से तो मेरी इतनी तवक्को नहीं है--लेकिन हम कल प्रेजीडेंट से मिले हैं--प्रेजीडेंट ने हमें यकीन दिलाया है कि वो प्राइम मिनिस्टर साहब से बात करेंगे और गवर्नर को कंवेंसिग करने से, डिले करने से रोकने के लिए प्राइम मिनिस्टर को कहेंगे--मैं ये अर्ज करना चाहता हूं-- या तो गवर्नमेंट की जानिब से वो उठ कर कह दें कि हमने गवर्नर को इंस्ट्रक्शन दिये हैं--

to ask the elected leader to form the Government. If they convince us on this, we will stay in the House. Otherwise, we will walk out of the House. I do not want to hear any lectures or speeches from them.

मुख्तसर बात यह है--क्या इन्होंने इंस्ट्रक्शन दिये है गवर्नर को कि वे डेमोक्रेसी को रेसपेक्ट करे तब तो मैं इनकी तकरीर को सुनने को तैयार हूं--अगर ये कहने को तैयार नही हैं--वो तो हमें मालूम है कि यही लोग प्रेशेराइज़ कर रहे हैं--तो हम तकरीर सुनने को तैयार नहीं हैं ।]

SHRI S. D. PATIL: Sir, I am rather surprised that the hon. Member from the other side has given a long sermon before I could complete my statement. We are not issuing any instructions to the Governor because... (*Interruptions*)

(*At this stage, some hon. Members left the Chamber*)

The Governor has to act according to his discretion and according to the Constitution. The Government of India is not going to issue any instructions to the Governor because he has to act contitutionally. He has got full discretion. The other side exhibited impatience. The Governor has to verify. The unfortunate part is that some Members have signed both the lists. There is a complaint that the names of some Independents figure in both the lists.

SHRI BHUPESH GUPTA: You have made that point. I do not dispute that.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please do not interrupt.

THE MINISTER OF RAILWAYS (PROF. MADHU DANDAVATE): Mr. Bhupesh Gupta, when you spoke, none of us intervened. Let him complete his statement.

SHRI S. D. PATIL: Five Members have signed both the lists. Now, he has to verify whether these names are overlapping and whether they are on this or on the other side. There are also allegations of duress that some

[Shri S. D. Patil]

Members were confined in a certain place and that they were not allowed to go. The Governor has to find this out, satisfy himself and he has to be clear on this point. If some time is taken in this, this should not be considered as something undemocratic. We have full faith in the honesty and in the intergrity of the Governor. Sir, we are firm believers in democracy. We do not want to make any departure from democracy. The Government of India does not come in here because the Governor has to act in accordance with articles 163 and 164 of the Constitution and he is acting accordingly. If there is a delay of one or two hours, this should not be made much of. Let us hope that he will act properly, honestly and constitutionally.

SHRI BHUPESH GUPTA: Sir, I have to make a submission. What about my motion?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I will consider this.

SHRI BHUPESH GUPTA: I have to submit . . .

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Do you want to mention your other subject?

SHRI BHUPESH GUPTA: Sir, you give the permission. Why can't you take the vote of the House?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I am not giving you any permission. I am not allowing it to be presented to the House.

SHRI BHUPESH GUPTA: Under what rules?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Are you going to speak on your subject?

SHRI BHUPESH GUPTA: Under what..

श्री उपसभापति : सदन की कार्यवाही दो बजे तक के लिये स्थगित की जाती है ।

The House then adjourned for lunch at six minutes past one of the clock.

The House reassembled after lunch at two minutes past two of the clock, **Mr. Deputy Chairman** in the Chair.

SHRI BHUPESH GUPTA: Sir, I would ask you to reconsider, or suggest any other means. We are in your hands. Sir, I would have normally not asked you. But you will well understand that the situation involves a certain very important matter in Maharashtra.

श्री सुलतान सिंह (हरयाणा) : इसमें देर नहीं करनी चाहिए, वहां खरीद चल रही है ।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: We will consider this.

SHRI NRIPATI RANJAN CHOUDHURY (Assam): When will it be considered?

SHRI BHUPESH GUPTA: Whichever way you like, Sir.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: We will consider your request.

SHRI NRIPATI RANJAN CHOUDHURY: This matter cannot be kept pending, Sir.

SHRI BHUPESH GUPTA: Sir, it is a strange thing. The Chair should kindly consider it. Here, the overwhelming majority—I use the word 'overwhelming'—of the Members of the House feel in a particular way. They request the Chair to kindly concede to their request and demand. And the demand is something not unheard of. We cannot have an Adjournment Motion. It is not provided under the Rules. Of course, I entirely agree with you. I cannot move any motion at this stage without your permission. Nor can you allow such a motion, rules being what they are. A notice is needed. But,

Sir, you have the power to ask the opinion of the House as to whether the Rules should be waived and to allow the discussion. Why should you take upon yourself the burden of denying us what most of us are demanding? If you think that the House is against it, if you sense that way, don't allow it If you think and sense that the House likes it, then you allow it in this form, or any other form you like. And nothing should be allowed to come in the way. This is what I am requesting you.

You know very well what has happened. The House can—I am not saying that—by a majority motion remove the Deputy Chairman. Such is the position of the House. Now if this be the right of the House—I am not saying that, Sir; least of all; it should not be taken as any reflection on you; I would be the last person to be a party to a motion that seeks your removal; I am saying this only to stress the importance of the House, the majority and the overwhelming majority opinion—is it right that the Chair should tread against the majority of the House? Is it a good parliamentary practice? Is it according to the conventions that the Chair, in order to please—I do not say you are pleasing—as if to please the Government, which is a minority in this House, as an overwhelming number—more than 200—are on this side—I say that if I have a lesser majority in the House than five or six times of their side, I will withdraw this motion.

SHRI SANKAR GHOSE (West Bengal): I am supporting Mr. Bhupesh Gupta on this because...

SHRI BHUPESH GUPTA: You consider it. We are in an unprecendented situation The House is in an unprecedented situation. What is the use of your giving permission after the Maharashtra problem takes a certain serious turn and the President's Rule comes? What is the use of our intervening then? Now is the time to intervene in this matter. We have raised certain points, constitutional and legal. We contested the election in Maharashtra and got only one seat. Therefore, I am not interested that way. I am here interested in a procedure being followed, in the Constitution being observed and practices being followed as conforming to democratic standards. If by following the Constitution the Janata comes into power, it is all right. Let the Janata come to power. But if by following that any other party comes or a combination of parties comes into power, the Governor should allow them to do so. Let it be decided on the floor of the House. I say, Sir, the Governor is provoking this kind of situation, this kind of horsetrading. His attitude is encouraging horse-trading. Is that the way for the Goveror to function? The difficulty arises when some feel that elected Members should go before the Governor. Does it conform with the dignity of the Members of a Legislature? I would ask my Congress friends and others not to go in for the parading business. This is undignified.

You say objective test. But the objective test is not there. An Assembly has been constituted. Let them go there What is the harm? If suppose some party is not in a position to muster majority the Governor will be entitled to call the next party, the Leader of the Opposition to form the Government This is the Parliamenttary practice. I am not bothered about which party he calls. Here, of course, the two Congresses are there. They can be called. If they are not in a position to show majority on the floor of the House, let the Janata leader be called. But that position is not being taken. This is my objection.

One point Mr. Pratap Chandra reminds me. In West Bengal in 1967 – I forgot to mention—the Congress Party did not want to form the Government. Having lost the majority they said they would not form the Government. They got 103 seats out

[Shri Bhupesh Gupta]

of 280. And the Opposition blocs combined got the majority. They conceded majority. You can cite other similar examples Therefore, from other points of view this matter should be discussed.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: That is what we are doing.

SHRI BHUPESH GUPTA: We are not. I will tell you why. You have been good enough. I am not complaining against you. I am not complaining on that score. Let the Government party come and explain the position. Let a debate take place over this matter and, if necessary, we move a motion expressing our disapproval of the conduct of the Government. We are expressing the disapproval of the attitude and conduct of the Government of India in this matter. If that is our right, will you allow such a motion to be moved? I know your hands are tied. Why should you do so? May I ask why? Why should the Chairman do it? You have to travel there in a corner to find the Government. You have to go round the Cape of Good Hope to discover some island in the Indian Ocean that there is a Government side in the House. Such is the position of the House. Must you go round the Cape of Good Hope, to discover the Government support, forgetting all the continents and sub-continents sitting here? We are in sub-continents and continents and you go this way. Sir, is that the way to function in the office of the Chair? Consider yourself, come to your own judgment.

MR DEPUTY CHAIRMAN: Please be brief.

SHRI BHUPESH GUPTA: Therefore, Sir, I know, perhaps you are embarrassed because of your party affiliation. Forget about your party affiliation.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please do not make any reference like that

SHRI BHUPESH GUPTA: I am not making...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: This is very unfair.

SHRI BHUPESH GUPTA: Why should it be unfair?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please resume your seat.

SHRI BHUPESH GUPTA: You should be biased towards us then. I am not making. It is a credit for you.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please, no credit or discredit, leave the Chair as it is.

SHRI BHUPESH GUPTA: All right, Sir, you are not in need of credit or discredit I understand. But I never made any reflection on you because normally you are doing things well out of your generosity and nothing else. But that generosity is very costly for us. This is what I am complaining about, Sir. There should be some cost accounting in this matter. The generosity should not be at our cost. This is what I say. Therefore, Sir, allow a discussion and you will see how the Government speaks and how we speak. Why are they shying away from a discussion?—I cannot understand. They have fled the Treasury Benches, most of them. Why? Tell us how to proceed in this matter. You guide us. You have the rules; you have the authority; you have the power I am no party in this matter. I am only interested in the rules, procedures, conventions, constitutional practices and nothing else. I am certainly against a situation which may lead to President's rule. The technique may be that nobody is in a position to form a Government. A report may come and then, temporary President's rule, then permanent President's rule All these things we should avoid. We should intervene at this stage to prevent President's rule and then leave it to the newly constituted Assembly. The Governor can do it even now. Let

him announce, "I am giving you the chance and you will have to call the Assembly to prove your majority." That will be the forthright way. This Presidential rule, President's intervention—all these things—must go now from the Constitution. You can discuss these things. But I again appeal to you in all humility, we need not have a demonstration here on the floor, least of all when you are in the Chair, or anybody is in the Chair, but I do maintain that we are in our right, we are under obligation that this matter be taken up by adjourning the business of the House, not in the technical adjournment sense, by your permission on the basis of a special resolution when the matter could be thrashed out. Let the country know who has got a better case in this matter. Let the people know.

SHRI SANKAR GHOSE: I fully support Mr. Gupta in this.

SHRI BHUPESH GUPTA: Let us take the verdict of the people, apart from other considerations, who is right on questions of principle, practice and norms that should be observed. Sir, the nation will judge We speak here before the bar of the nation and we shall have the verdict of the nation also in this matter. But let people judge why this thing is going on.

We are not interested in signing and countersigning, producing two or three lists, with some people signing on more than one list. This is horse-trading. I make the Governor responsible for encouraging this kind of malpractice. Sir, this is all I say.

Again, Sir, I beseech you, I appeal to you with all the persuasive power at my command, that you kindly consider giving us an opportunity to discuss it immediately. If not immediately, take a little time, a few hours Let the matter come.

Is it proper that the Prime Minister does not even come to this House whereas, I am told, he has made a certain statement in the other House? Does he know that this House also is agitated? Must he not at least come here once? That is for you to ensure. Why can't you direct the Government to bring the Prime Minister here and let the Prime Minister say what he has to say? Why is he not coming to this House?

Sir, are we an empty Chamber of Parliament? Or, are we one of the two Houses of Parliament? Are we an empty Chamber to be kept waiting on the pleasure of the Prime Minister? Or, have we got the right to have the Prime Minister to be heard on the subject? That also is a question I put before you. Sir, all kinds of problems have arisen, questions of propriety have arisen, including the absence of the Prime Minister from this House. You should settle it. Please do not allow it to go on in this manner. I had talked during the lunch hour with all Members, five Independents and others also. I can tell you on their authority that there is no dispute.... (*Interruptions*)

SHRI SANKAR GHOSE: So far as this motion is concerned....

श्री भीष्म नारायण सिंह : उपसभापति महोदय, श्री भूपेश गुप्त जी का जो प्रस्ताव है, मैं उसका समर्थन करता हूं और... (*Interruptions*)

श्री कल्पनाथ राय : (उत्तर प्रदेश) : आदरणीय उपसभापति महोदय, भूपेश गुप्त जी ने जो कहा है, उसका हम समर्थन करते है।

SHRI SANKAR GHOSE: Sir, so far as this motion is concerned, if we discuss sports when democracy is on bonfire in Maharashtra, posterity will say that Parliament was fiddling when Maharashtra was burning. Is this the thing to be done? Will Parliament fiddle? Sir, because of the great respect and regard we have for you, and because of the ample power you have

[Shri Sankar Ghose]

under the Rules, we have to see that today we do not discuss sports but we discuss something which deals with the future of the country, which is stability of democracy with the role of the Governor. The Governor is being pressurised from the Centre. All talk of democracy is going on. Now, if today we find any hesitation after physical demonstration, after physical verification, what is the hesitation for? Is the hesitation for creating stability in Maharashtra? Is the hesitation.. (*Interruptions*). Is the hesitation for bringing about horse trading in Maharashtra? If we do not discuss these things today, posterity will say that on that solemn day Parliament did not discuss Maharashtra, but discussed sports and games and football. This is what the future will say. Should we allow democracy to burn? Should we allow Maharashtra to burn? Even now the Prime Minister has not come. No statement has been made from the Government side. Our allegation is clear. We are saying that the Governor is being pressurised by certain elements in the Central Government. We want a clear, categorical statement from the Central Government that the Governor will act according to democratic norms, according to Constitutional procedures. This is an old convention of 50 years. You know, Sir, when this convention was established. This convention was established when a socialist Government was formed in Britain for the first time. When was the Labour Government formed in Britain for the first time? In 1920's. Who got the majority? The largest single party was the Conservative Party. Was the Conservative Party called to form the Ministry? No. The second largest party was the Labour Party. The third largest party was the Liberal Party. Though the Conservative Party led by Stanley Baldwin was the largest single party in the House of Commons, he was not called to form the Government. The Labour Party was called to form the Government because the Labour Party in alliance with the Liberals had the majority. Under the Constitution, what has to be seen is that the Ministry is responsible to the Assembly. If the Ministry is responsible to the Assembly, the only thing to be seen is whether it has got the majority support. When the majority support has been proved conclusively, physically, overwhelmingly, there is this apprehension. There are some Ministers—I can name them—who are sitting in Maharashtra—the Janata Ministers—trying to pressurise the Governor. Is this not a matter which the House should debate? Sir, you have the power. If you did not have the power, I would not have asked you to consider this. If you did not have the power, I would not have raised this question. The real question is: If you have power, what is the priority, what is the practice? Today, should we discuss sports or should we discuss democracy? Should we not discuss the destruction of democracy in Maharashtra? Therefore, this is my request to you. You have the power, you have the discretion. Please exercise that power.

SHRI BHUPESH GUPTA: Sir, you consider allowing a discussion on the situation arisen in Maharashtra. There are many ways. It is for you. I request you, Sir, to kindly adjourn the House for ten minutes. Let us go into your chamber. (*Interruptions*) Let it not be said that when Rome was buring, Nero was fiddling. I suggest you to adjourn the House for 10 to 15 minutes.

SHRI MOHAMMAD YUNUS SALEEM (Andhra Pradesh): You take the sense of the House.

श्री कल्पनाथ राय : आदरणीय उपसभापति महोदय, भूपेश गुप्त साहब ने जो प्रस्ताव रखा है, मैं उसका समर्थन करता हूं। पहली जनवरी, 1978 को कातिल की तलवार कर्नाटक की सरकार पर उठी थी। कर्नाटक की सरकार को पहली जनवरी, 1978

को चौधरी चरण सिंह और प्रधान मन्त्री के इशारे पर बर्खास्त किया गया था। कातिल की तलवार से जनतन्त्र का गला पहली जनवरी को काटा गया था। यदि इस कातिल की तलवार को नहीं रोका गया तो आज नहीं कल यह बहुत सी राज्य सरकारों का खात्मा करेंगे। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि गवर्नर बिल्कुल चौधरी चरण सिंह का प्रतिनिधि बन कर कांग्रेस सरकार को गिराने की कोशिश कर रहा है। महाराष्ट्र के अन्दर जहां 149 लोगों ने प्रेड की वहां सादिक अली साहब जो गवर्नर है उन्होंने अब तक भी सरकार को बनाने की आज्ञा नहीं दी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या इस तरह से प्रजातान्त्रिक मान्यताओं की रक्षा हो पायेगी? आदरणीय उपसभापति महोदय, 149 एम० एल० एज़० ने रेप्रेसेंटेशन किया, प्रदर्शन किया, इसके बावजूद भी अब तक गवर्नर ने सरकार बनाने के लिए नहीं बुलाया। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि गवर्नर आज बिल्कुल गृहमन्त्री चौधरी चरण सिंह के इशारों पर है कर्नाटक की सरकार को गोविन्द नारायण ने बर्खास्त किया। मैंने सदन में मांग की थी कि गोविन्द नाराण को बर्खास्त किया जाए। अब मैं मांग करता हूं कि सादिक अली को प्रधान मन्त्री और गृह मन्त्री बर्खास्त करे क्योंकि वह कांग्रेस की हकूमत को महाराष्ट्र में बनाने में बाधा डाल रहा है। यदि सरकार ने भूपेश गुप्त साहब के इस प्रस्ताव पर पूरी बहस की इजाज़त नहीं दी तो हम सदन को नहीं चलने देंगे।

SHRI NRIPATI RANJAN CHOUDHURY: Sir, you take the sense of the House. The House is not in a mood to discuss sports. Democracy is being killed in Maharashtra, Sir, and you have got a specific suggestion from Shri Bhupesh Gupta to adjourn the House for ten minutes, discuss with the leaders of the different parties and then allow us a discussion on the situation in Maharashtra.

Sir, I tell you, now it is time that we should hear from you, but I want to express my mind and also the mind of my party. Whether you allow it or not, you cannot force us to discuss something. So, our sentiment is that we will not allow Parliament to go on fiddling when Maharashtra is burning. So, Sir, if you do not like us to discuss on the situation in Maharashtra, we are not going to discuss sports. By that way we will register our protest, Sir. You may or may not allow us to discuss the situation in Maharashtra. You may order the House to discuss sports. But, I tell you, Sir, we the Members on this side are not going to participate in the discussion on sports and will register our protest. Now it is for you to decide. A concrete suggestion is there from Shri Bhupesh Gupta. Kindly let us know your mind, Sir.

श्री कल्पनाथ राय : उपसभापति महोदय, प्रधान मन्त्री और गृह मन्त्री को बुलाया जाये।

SHRI BHUPESH GUPTA: Sir, you are in a very difficult position. I have suggested adjournment. Suppose the House is adjourned.. *(Interruptions)*

श्री रामानन्द यादव : उपसभापति जी, भूपेश गुप्त जी ने जो रिजोल्यूशन सदन के सामने रखा है उसका मैं समर्थन करता हूं, अपने साथियों के सार्थ समर्थन करता हूं। इस रिजोल्यूशन पर बहस होनी चाहिए, यह बहुत भयंकर बात है। आज प्रजातन्त्र खतरे में है। जिन लोगों ने श्रीमती इन्दिरा गांधी को तानाशाह कहा था तथा तानाशाह कह कर, जनता को भ्रांति में डाल कर, जीत कर आये थे जनता के वोट से आज वही प्रजातन्त्र के रक्षक प्रजातन्त्र के भक्षक हो गये है। 12 प्रान्तों में एक बार और फिर कर्नाटक तथा आज महाराष्ट्र में बन रहे हैं। उपसभापति जी आपको मालूम है कि गवर्नरस की कांफ्रेंस में डिसीजन हुआ था कि इस हाऊस का स्ट्रेन्थ, लीडर का स्ट्रैन्थ, पार्टी का स्ट्रैन्थ

[श्री रामानन्द यादव]

सब हाउस में वोट के आधार पर तय होगा लेकिन कर्नाटक में इस आधार पर वहां के गवर्नर ने राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन के लिए लिखा कि सम्भव है कि समय मिलने पर वोटों की खरीद बिक्री शुरू हो जाय। इसलिए अर्स साहब की मिनिस्ट्री को जल्दी खत्म कर दिया जाय और राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाय। वहां राष्ट्रपति शासन लागू भी कर दिया गया। यह भी आपको मालूम है, उपसभापति जी, कि किस तरह से गवर्नर ने अपनी सारी पावर्स को प्रजातन्त्र की हत्या करने के लिए कर्नाटक में यूज किया और यह गवर्नमेंट बैठी यहां से रेडियो के द्वारा प्रतिदिन बयान करती थी। चुनाव के वक्त में उसके जो पक्षधर नेता हैं अर्स साहब उनके खिलाफ केस करने का गवर्नर बयान करते थे, आर्डर करते सें, रेडियो से ये बयान होते थ। आप सोचें कि किस तरह से सरकारी मशीनरी का उपयोग जनता को गुमराह करने के लिए इस तथाकथित प्रजातान्त्रिक सरकार ने किया? गवर्नर के जो इंस्टीट्यूशनल पावर्स है जिनको होली इंस्टीट्यूशन कहने से हम नहीं चूकते हैं आज हम उसे प पी इंस्टीट्यूशन कहने के लिए तैयार हैं क्योंकि उसका भ्रष्ट ढंग से उपयोग किया गया है। महाराष्ट्र को ले लीजिए, महाराष्ट्र मे 149 कांग्रेस के सदस्यों ने जाकर गवर्नर साहब के सामने परेड की। मैं परेड को बुरा मानता हूं। मैं भूपेश गुप्त के साथ हूं कि एक लाख, डेढ़ लाख जनता चुनती है, चुन कर आदमी जाता है और इस नामिनेटेड आदमी, गवर्नर के सामने विधायकों को फिजिकली वैरीफिकेशन करना पड़ता है।

श्रीमती सरोज खापर्डे (महाराष्ट्र): गवर्नर के साथ उनका फोटो भी लिया गया था।

श्री रामानन्द यादव: यह महाराष्ट्र की जनता का अपमान है। उस जनता का अपमान है जिसने अपने बालिग मताधिकार के आधार पर अपने नुमाइन्दे को चुना। उन नुमाइन्दों को गवर्नर अपने सामने बुलाता है, यह टेस्ट करता है कि तुम किधर हो। जो गवर्नर्स का कावेंशम था उसके बारे में उनकी एक मीटिंग काश्मीर में हुई थी। वहां सारे प्रान्तों के गवर्नर इकट्ठा थे उन्होंने कोड आफ कन्डक्ट इवाल्व किया कि इस परिस्थिति में गवर्नर क्या करेगा? यह फैसला हुआ कि हाउस के फ्लोर पर पार्टी की स्ट्रैन्थ आंकी जायगी। इसलिए जब कांग्रेस पार्टी के सदस्यों ने, एक नेता ने 149 सदस्यों का प्रदर्शन किया—प्रदर्शन नहीं करना चाहिए था यह अच्छा नहीं है—लेकिन अगर प्रदर्शन कर भी दिया जाय तो फिर इस बात को मानने से गवर्नर ने क्यों इंकार किया? इससे साफ मालूम होता है कि गवर्नर मिले हुए हैं एक गवर्नर कर्नाटक में कहते हैं कि समय दिया गया तो रुपये पैसे से खरीद फरोख्त शुरू हो जायगी। मुझे मालूम है कि अमेरिका की हवा वहक कर बम्बई में जल्दी आ जाती है और बम्बई थैली शाहों का घर है। यह सरकार जो थैली शाहों के बल से, साम्राज्यवादियों के बल से, साम्प्रदायिक तत्वों के बल से, पूंजीपतियों के बल से इस सत्ता में आयी हुई है और जिनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, सत्ता का दुरुपयोग करेगी, पैसे का दुरूपयोग करेगी। मुझे उम्मीद है कि चाहे वे इस सदन के हों या उस सदन के, महाराष्ट्र के विधायक चाहे इस पार्टी के हों या उस पार्टी के वे खरीद फरोख्त में नहीं आयेंगे, इनकी चाल में नहीं आयेंगे, मुझे उनके प्रति सम्मान है। लेकिन इस गवर्नमेंट की नीयत साफ नहीं मालूम देती है। मैं आपसे मांग करता हूं कि भूपेश गुप्त जी का जो रिजोल्यूशन है, उस पर आप बहस कराईये मैं दूसरी मांग यह करता हूं कि यह सरकार महाराष्ट्र के गवर्नर को बरखास्त करे या वहां से लौटा दे।

श्री कल्पनाथ राय : उपसभापति महोदय, महाराष्ट्र के गवर्नर को बर्खास्त करिए ।

SHRI MOHAMMAD YUNUS SALEEM: Whatever is happening in Maharashtra is alarming . . .

श्री आर० डी० जगताप आवरगांवकर : (महाराष्ट्र) : मैं महाराष्ट्र से आता हूं, मुझे महाराष्ट्र के बारे में कहने दीजिए । वहां पर जो जम्हूरियत का गला घोंटा जा रहा है और सादिक अली साहब जमहूरियत के नाम पर जनता सरकार के इशारे पर ख्वामख्वाह वहां की जो मजारिटी है उसको खत्म करने के लिए मांग स्वीकार कर रहे हैं इसलिए मे आप से... *(Interruptions)*

श्री उपसभापति : माननीय सदस्य इस विषय पर काफी बोल चुके हैं । अब सदन की कार्यवाही निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार चलनी चाहिए ।

(Interruptions).

श्री नृपति रंजन चौधरी : इस तरह से हम कार्यवाही नहीं चलने देंगे । यह मनमानी नही चलेगी । इस पर बहस होगी । नहीं तो सदन नही चलेगा ।

(Interruptions)

श्री कल्पनाथ राय : आप इस पर बहस कराइए वरना यह सदन नही चलेगा ।

SHRI BHUPESH GUPTA: No business can be conducted today, unless...

(Interruptions)

श्री उपसभापति : एक मिनट ठहरिए । सदन की कार्यवाही बगैर माननीय सदस्यों के सहयोग से नही चल सकती और ऐसा प्रतीत होता है काफी तादाद में बहुत से माननीय सदस्य हैं जो सदन की कार्यवाही को निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार नहीं चलने देना चाहते हैं । इसलिए सदन की कार्यवाही 8 तारीख प्रातःकाल 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है ।

The House then adjourned at thirty-two minutes past two of the clock till eleven of the clock on Wednesday, the 8th March, 1978.

GMGIPMRND—RS II—1972 RS—1-6- 78—595.